



# CURRENT AFFAIRS

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

**DATE: 26-06-25** 







# The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE Thursday, 26 June, 2025

## **Edition: International Table of Contents**

| Page 01                        | 41 साल के अंतराल के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में, |
|--------------------------------|--|
| Syllabus : GS 3 : Science &    | ıss मिशन पर  |
| Technology                     |  |
| Page 01                        | भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गई कीमोथेरेपी दवाएँ गुणवत्ता     |
| Syllabus : GS 3 : Science &    | परीक्षण में विफल रहीं: अध्ययन                                |
| Technology                     |  |
| Page 08                        | पश्चिम एशिया संघर्ष में 'उथल-पुथल की धुरी'                   |
| Syllabus: GS 2: International  |  |
| Relations                      |  |
| Page 07                        | प्रवासियों के लिए मतदान का अधिकार सक्षम करना                 |
| Syllabus: GS 2: Indian Polity  |  |
| Page 10                        | क्या जाति की गणना करने की पद्धति बदलनी चाहिए?                |
| Syllabus: GS 2: Social Justice |  |
| Page 08 : Editorial Analysis:  | एक उच्च अवधारणा, एक राज्यपाल और अवांछित विवाद                |
| Syllabus: GS 2: Indian Polity  |  |
|                                |  |





## Page 01: GS 3: Science & Technology

बुधवार को, भारत ने अपने अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को Axiom-4 (Ax-4) मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजा गया। यह 41 वर्षों में पहली बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया है, और विशेष रूप से, यह पहला मौका है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री ISS पर गया है।

# Indian astronaut in space after 41-year gap, on mission to ISS

Start of India's human space programme, says Shubhanshu Shukla as Axiom-4 mission is launched from the Kennedy Space Center, U.S., a four-member crew will spend 14 days in orbit conducting science, outreach, and other commercial activities

International

**Space Station:** 

capsule housing

the 4 astronauts

The SpaceX

Dragon crew

is targeting

to dock at the

International

Space Station at

approximately

4.30 p.m. IST

on Thursday

journey

after a 28-hour

#### Hemanth C.S.

BENGALURU

ndia's human space programme took off on Wednesday as Indian astronaut Shubhanshu Shukla's Axiom-4 mis-(Ax-4)International Space Station (ISS) was launched from NASA's Kennedy Space Center in Florida, U.S., after multiple delays.

"This is not the start of my journey to the ISS but the start of India's human space programme. I want my countrymen to become part of this journey, let us join together and start India's human space programme. Jai Hind Jai Bharat," Group Captain Shukla said in his first message from the mission.

Group Captain Shukla, the pilot of the Ax-4 mission, began a 28-hour journey to the orbiting labora-

## Above and beyond

Group Captain Shubhanshu Shukla becomes the first Indian to reach space in 41 years after the Axiom-4 mission lifted off from the Kennedy Space Center in Florida on Wednesday



From left: Tibor Kapu (Hungary), Mission Specialist; Shubhanshu Shukla (India), Pilot; Peggy Whitson (U.S.), Commander; and Sławosz Uznański-Wiśniewski (Poland), Mission Specialist

After 40 years we have once again reached space and it was an amazing ride...This is not the start of my journey to the ISS but the start of India's human space programme

GROUP CAPTAIN SHUBHANSHU SHUKLA, Mission Pilot

tory in space along with Commander Peggy Whitson (U.S.), Mission Specialist Sławosz Uznański-Wiśniewski (Poland), and

Mission Specialist Tibor Kapu (Hungary).

The SpaceX Dragon crew capsule housing the astronauts is targeting to dock at the ISS at approximately 4.30 p.m. IST on Thursday.

After docking, the crew

days aboard the ISS conducting science, outreach, and other commercial activities. The Ax-4 research complement includes nearly 60 scientific activirepresenting countries.

Upon docking, Group Captain Shukla will become the first Indian astronaut aboard the ISS, after having become the first Indian to reach space in 41 vears.



The Falcon 9 rocket carrying the astronauts in a SpaceX Dragon crew capsule lifted off from Launch Complex 39A at the Kennedy Space Center at 12.01 p.m. on Wednesday. Around 10 minutes after lift-off, the Dragon capsule separated from the second stage of the rocket and its nose-cone open sequence

Wednesday's

mission launch

launch planned on

2 The crew members will

conducting science,

commercial activities

The Ax-4 research complement

studies and activities

includes nearly 60

representing 31

countries

spend 14 days

aboard the ISS

outreach, and

May 29

comes after multiple

delays from the initial

members will spend 14

#### इस घटना का महत्व:

1. भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान आकांक्षाओं का पुनरुद्धार:

ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की पूर्ण मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की प्रतीकात्मक शुरुआत माना जा रहा है। अंतरिक्ष से उनका संदेश — "यह मेरी ISS यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है" — इस भावना को दर्शाता है।





#### 2. गगनयान की दिशा में रणनीतिक छलांग:

भारत का स्वदेशी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों (गगननॉट्स) को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का लक्ष्य रखता है। Ax-4 मिशन दीर्घकालिक मानव उपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण संचालन अनुभव प्रदान करता है, जो गगनयान के लिए एक पूर्वाभ्यास के रूप में काम करेगा।

3. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:

यह मिश्रन Axiom Space की वाणिज्यिक परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, पोलैंड, हंगरी और अब भारत भी शामिल है। यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक वाणिज्यिक और वैज्ञानिक अंतरिक्ष पहलों में भाग लेने के लिए तैयार और सक्षम है।

4. विज्ञान कूटनीति और जनसंपर्कः

31 देशों सें 60 वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ, यह मिशन विज्ञान कूटनीति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें भारत की भागीदारी उसे माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिक्षा में वैश्विक अनुसंधान व नवाचार में ऊंचा दर्जा देती है।

5. जन प्रेरणा और सॉफ्ट पावर:

शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से युवाओं के बीच अंतरिक्ष अन्वेषण में रुचि और कल्पना को पुनः जागृत करती है। यह मिशन भारत की सॉफ्ट पावर और उभरती हुई अंतरिक्ष तकनीकी नेतृत्व की छवि को सुदृढ़ करता है।

## चुनौतियाँ और आगे की राह:

संस्थागत तैयारीः

जबिक इसरों ने अपने मानवरहित अभियानों में तकनीकी उत्कृष्टता प्रदर्शित की है, मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए उच्च सुरक्षा, जीवन समर्थन प्रणाली और क्रू प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। Ax-4 जैसे मिशन इस अनुभव अंतर को पाटने में सहायक हैं।

वित्तपोषण और वाणिज्यिक व्यवहार्यताः

भारत को अपने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करनी होगी और दीर्घकालिक आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक साझेदारियाँ तलाशनी होंगी।

वैश्विक मानकों और सततता:

मानव अंतरिक्ष मिशनों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चाहिए जैसे कि अंतरिक्ष मलबा, क्रू सुरक्षा और टिकाऊ कक्षीय प्रथाएँ।

बुनियादी ढांचे का विकास:

भारत को उन्नत अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधाएं, पुनः प्रवेश तकनीक, और वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों एवं निजी भागीदारों के साथ समन्वय की आवश्यकता होगी।

#### निष्कर्षः

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का Ax-4 मिशन पर सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं बल्कि मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षेत्र में भारत की गंभीर उपस्थिति की घोषणा है। यह मिशन केवल अतीत की गौरवगाथा का स्मरण नहीं, बल्कि भविष्य की महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक भागीदारी का संकेत है। UPSC उम्मीदवारों के लिए यह विकास भारत की अंतरिक्ष कूटनीति, तकनीकी प्रगति और सॉफ्ट पावर का एक प्रेरणादायक उदाहरण है।





#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques : "एक्स-4 मिशन में भारत की भागीदारी इसकी मानव अंतरिक्ष उड़ान यात्रा में एक नया अध्याय शुरू करती है।" भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए इस विकास के महत्व और गगनयान और उससे आगे के लिए इसके निहितार्थीं पर चर्चा करें। (250 Words)

#### Page 01: GS 3: Science & Technology

हाल ही में "द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म" (TBIJ) द्वारा द हिंदू के सहयोग से की गई एक जांच में यह खुलासा हुआ है कि भारतीय निर्माताओं द्वारा उत्पादित जेनेरिक कीमोथेरेपी दवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षणों में विफल रहा है। ये दवाएं, जो स्तन, डिम्बग्रंथि (ओवेरियन) और ल्यूकेमिया जैसे कैंसर के इलाज के लिए आवश्यक हैं, 100 से अधिक देशों में निर्यात की जाती हैं. जिनमें विकासशील देश भी शामिल हैं जहां नियामक निगरानी की क्षमता सीमित है।

## Chemotherapy drugs made by Indian companies fail quality tests: study

Andjela Milivojevic Ramu Sapkota

Vital chemotherapy drugs used around the world have failed quality tests, leaving cancer patients in more than 100 countries at risk of ineffective treat-ments and fatal side effects, the Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) can reveal.

The drugs in question form the backbone of treatment plans for numerous common cancers including breast and ovarian cancers and leukaemia. Over the past six years, they have been shipped to countries such as Nepal, Ethiopia, the U.S., the U.K., and Saudi Arabia.

The test findings come from a study by researchers at the University of Notre Dame in the U.S. who analysed 189 samples

of various cancer drugs. About one-fifth failed.

The worst-performing drug in the study is made by Indian manufacturer Venus Remedies. All eight samples of the company's cyclophosphamide product failed.

Venus Remedies told TBIJ that the test results "not scientifically plausible" given the com-pany's "validated manufacturing systems and quality controls". It said it has received no complaints or concerns about the batches in question and shared the results of its own testing that indicated they were of a good stan-

Faulty storage blamed

The manufacturer said storage conditions in the supply chain – which can impact drug quality – might have affected the re-

searchers' test results. Ho wever, the absence of similar quality issues across the entire data set suggests this is not the case. Venus Remedies is one

of three companies or regulators that queried the methodology used by the lab, saying it deviated from international standards or could give erroneous results. However, Maria Lie berman, who led the research. said researchers' methods folinternational standards as closely as possible and employ similar standards to a regulatory lab. Both the findings and methods have been scrutinised by independent

Two other manufacturers whose products failed the testing, Zuvius Lifesciences and GLS Pharma, have supplied failed brands to over 40 coun-



Marya Lieberman, the Notre Dame professor who led the rese at work in her lab. UNIVERSITY OF NOTRE DAME

tries. Of the 17 companies that manufactured failed drugs, 16 are based in

Some drugs contained so little of their key ingre-dient that pharmacists said giving them to patients would be like doing nothing.

Other drugs, containing too much active ingredient, put patients at risk of severe organ damage or even death. "Both scena-rios are horrendous," said vice-chair of the British Oncology Association.

Zuvius Lifesciences. GLS Pharma, and Zee Laboratories did not respond to multiple requests for comment.

Doctors from multiple

countries told TBIJ of the drugs in question not working as expected, leaving patients suddenly unonsive to treatment. Other patients suffered side effects so toxic they could no longer tolerate the medicine.

The findings expose holes in the global safety nets intended to prevent profit-seeking manufacturers from cutting corners and to protect patients from bad drugs. More than two in three countries around the world are re-portedly unable to ensure the quality of medicines their populations are exposed to.

Nepal was one of the biggest importers of the failed chemotherapy brands in this investigation. The country's medicines regulator does not have the capacity to test cancer drugs. Although it can recall cancer drugs based on external dence, it has never done

"Neither patients nor their families have any way of knowing the quality of Pokharel of the Wish Nepal Foundation "No one Foundation. seems willing to take responsibility for ensuring proper treatment for cancer patients."

Much of the global demand for cancer treatment is met by generic drugs -which the low-quality which drugs found in this investigation were.

In India, the world's largest producer of generic drugs, questions have been raised over whether manufacturers are properly pun-ished for producing such bad drugs.

"The Indian govern-ment's interest is in trying to protect the industry,

said public health activist Dinesh Thakur.

India's drug regulator defended the oversight system, saying that failing drugs are recalled and manufacturers face "either administrative penalties or legal prosecution

Thakur pointed to limitations in the World Health Organization's means of ensuring people across the world have access to safe effective drugs. The WHO did not respond to several requests for comment.

One cancer pharmacist in Ethiopia estimated that it could take over a year for a patient to save for cancer treatment. If that medicine then turns out to be faulty, they simply might not be able to afford to pay for another.

(This article is jointly pu-blished by The Hindu and

## मुख्य बिंदु:

#### सार्वजिनक स्वास्थ्य का खतराः

आवश्यक कीमोथेरेपी दवाओं की विफलता जानलेवा जोखिम उत्पन्न करती है। जिन दवाओं में सक्रिय घटक की मात्रा बहुत कम होती है वे उपचार को अप्रभावी बनाती हैं, जबिक अधिक मात्रा वाली दवाएं घातक विषाक्तता का कारण बन सकती हैं। यह सीधे तौर पर कैंसर रोगियों को खतरें में डालता है, जो पहले से ही इलाज की लागत और मानसिक तनाव के कारण कमजोर स्थिति में होते हैं।

2. भारतीय फार्मा उद्योग की साख को नुकसान:

भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का आपूर्तिकर्ता है, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक स्थिति रखता है। इस प्रकार की घटनाएं भारतीय फार्मा उद्योग की साख को कमजोर करती हैं और गुणवत्ता, नियामक निगरानी और नैतिक विनिर्माण प्रथाओं पर संदेह खड़ा करती है।





#### 3. नियामक विफलताएँ:

भले ही भारत का औषिध नियामक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रिकॉल और कानूनी अभियोजन जैसे उपायों का दावा करता हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार-बार परीक्षणों में विफलता से यह स्पष्ट होता है कि प्रवर्तन, निगरानी और उत्तरदायित्व के तंत्र में गंभीर खामियां हैं।

#### 4. वैश्विक स्वास्थ्य में असमानता:

नेपाल और इथियोपिया जैसे देश सस्ती उपलब्धता के कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं। हालांकि, इन देशों में परीक्षण अधोसंरचना और नियामक क्षमता की कमी के कारण निम्न-गुणवत्ता वाली दवाएं सबसे हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुँचती हैं — जिससे वैश्विक स्वास्थ्य असमानताएं और गहरी होती हैं।

5. फार्मास्युटिकल व्यापार का नैतिक पक्ष:

विकासशील देशों को निम्न-गुणवत्ता वाली कीमोथेरेपी दवाओं का निर्यात एक नैतिक विफलता को दर्शाता है। यह लाभ को मानव जीवन से ऊपर रखने की मानसिकता को इंगित करता है और कड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों, नैतिक व्यापार प्रथाओं और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

6. अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका:

यह खुलांसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसी संस्थाओं की वैश्विक दवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। इस मुद्दे पर WHO की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति वैश्विक उत्तरदायित्व ढांचे और निम्न व मध्यम आय वाले देशों (LMICs) में रोगी सुरक्षा को लेकर चिंताएं उत्पन्न करती है।

#### चुनौतियाँ और प्रणालीगत खामियाँ:

- उत्पादन के बाद परीक्षण और फार्माकोविजिलेंस की अपर्याप्तता।
- मरीजों के स्तर पर जागरूकता या कानूनी उपायों की कमी।
- पारदर्शिता की कमी और निर्माताओं की उत्तरदायित्व स्वीकारने में अनिच्छा।
- अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियामक निकायों के बीच कमजोर समन्वय।
- सीमित विकल्पों के साथ निम्न और मध्यम आय वाले देशों की कुछ आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता।

#### आगे की राह:

#### 1. घरेलु नियमन को सुदृढ करना:

भारत को अपने दवा निगरानी प्रणाली को उन्नत करना चाहिए, बैच परीक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए, कठोर दंडात्मक उपाय लागू करने चाहिए और अनुमोदन एवं रिकॉल प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।

#### 2. वैश्विक उत्तरदायित्व ढांचा:

एक अंतरराष्ट्रीय मंच की तत्काल आवश्यकता है जो सीमा-पार दवा सुरक्षा का मूल्यांकन करे, जिसे UN/WHO के तहत लागू किया जा सके और जिसमें निर्यातक देशों की बाध्यकारी जिम्मेदारियाँ निर्धारित हों।

#### 3. प्रौद्योगिकी-सक्षम गुणवत्ता नियंत्रण:

ब्लॉकचेन, एआई आधारित निगरानी और रीयल-टाइम बैच सत्यापन प्रणालियों का उपयोग दवा आपूर्ति श्रृंखला में घटिया दवाओं के जोखिम को कम कर सकता है।

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





4. आयातक देशों की स्थानीय क्षमता सुदृढ़ करना:

LMICs को अपनी प्रयोगशालाओं में निवेश करना चाहिए, सख्त आयात नियम अपनाने चाहिए और क्षेत्रीय दवा गुणवत्ता गठबंधन बनाना चाहिए।

5. **सार्वजिनक रिपोर्टिंग और व्हिसलब्लोअर सुरक्षाः** पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उन शोधकर्ताओं और फार्मासिस्टों की रक्षा की जानी चाहिए जो असुरक्षित या अनैतिक दवाओं की रिपोर्ट करते हैं।

#### निष्कर्षः

यह घटना कोई अलग-थलग विफलता नहीं है, बल्कि एक प्रणालीगत चेतावनी है। विशेष रूप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनी दवाओं की सुरक्षा और प्रभावशीलता से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत जैसे देश, जो वैश्विक फार्मेसी बनने की आकांक्षा रखता है, के लिए उसकी दवाओं की विश्वसनीयता केवल सस्ती कीमतों पर नहीं, बल्कि सुनिश्चित गुणवत्ता और नैतिक जिम्मेदारी पर आधारित होनी चाहिए।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: "फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखलाओं को विनियमित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सस्ती दवा का उत्पादन करना।" भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दवा गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए आवश्यक तकनीकी, कानूनी और नीतिगत उपायों की जाँच करें। (250 words)





#### Page: 08: GS 2: International Relations

हालिया इज़राइल और ईरान के बीच संघर्ष, जो अमेरिकी हवाई हमलों द्वारा ईरानी परमाणु स्थलों पर किए गए हमलों के कारण और बढ़ गया, ने उभरते वैश्विक शक्ति गुटों को लेकर तीव्र वैश्विक बहस को जन्म दिया है। पश्चिम विरोधी समन्वित गठबंधन— जिसे 'उथल-पुथल का अक्ष' (Axis of Upheaval) कहा गया है (ईरान, रूस, चीन और अन्य)—की धारणा पर सवाल उठने लगे हैं, विशेष रूप से तब जब रूस और चीन जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने ईरान की प्रत्यक्ष सहायता से दूरी बना ली है।

## The 'Axis of Upheaval' in the West Asia conflict

s the war between Israel and Iran has resulted in a ceasefire after being layered with America's bombing of Iran's nuclear sites, the narrative of the world being divided into power blocs like those during the Cold War era stands punctured. With Iran having suffered a political and military decapitation of leadership and capacity alike, its main partners, China and Russia, have maintained a distance. Before the conflict, Iran had been central to the narrative of the global order's perceived fracturing between palatable West-led alliances against a Moscowand Beijing-knitted axis, dubbed as the 'Axis of Upheaval' by American scholars Richard Fontaine and Andrea Kendall-Taylor.

In Russia's war against Ukraine, Iranian drone technologies have played a critical role, while Moscow and Tehran, despite certain regional differences, once joined hands to stabilise the government of the now ousted Syrian President, Bashar al-Assad. Meanwhile, as sanctions have gnawed at Iran's economic depth over the years, China has gained much by continuing to buy cheap oil from the country. This has been helpful to Beijing in powering its stagnating growth while giving Tehran much needed cash inflows in a polity and society that is starved of steady financial streams.

#### No treaties

However, all this balancing has strategic limitations as well. The axes, at best, are a narrative construct. There are no treaties that bind these states into military blocs, where charters can be mobilised to push the others to join a war if a partner country is attacked. The underpinnings of these partnerships nonetheless go deeper, spilling over into a reconstruction of institutions, currencies, multilateralism and how the world operates today. They want de-dollarisation, alternatives to western payments gateways such as SWIFT, and a strengthening of organisations such as BRICS and



Kabir Taneja

is Deputy Director and Fellow, Strategic Studies Programme, Observer Research Foundation

The narrative of the world being divided into power blocs like those during the Cold War era has been punctured the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) as well as fundamental anti-West ecosystems. But there is no military treaty to anchor all these, which marks a critical gap in taking on western influence which is pinned using both treaties and understandings.

Russia and China, nonetheless, have made statements in favour of Iran as a way of support. Moscow has criticised those backing Israel's actions, including the ambiguity of positions taken by the International Atomic Energy Agency and attempts to manipulate international non-proliferation regimes. Russia's President Vladimir Putin in a telephone call offered mediation, which was sidelined by United States President Donald Trump. The noticeable part was this: it was not that Mr. Putin wanted to mediate, but political and diplomatic support may be the only thing Russia may be able to offer Iran at this stage.

Tehran has comprehensive strategic partnerships that it signed with Mr. Putin (2025) and China's President Xi Jinping (2021), which are almost exclusively economic in nature. While aligning with Iran as part of an axis in the long term makes sense if one considers the country's vast energy reserves (many of which remain untapped due to technology-led roadblocks aided by international sanctions), the fact is that neither Russia nor China have the intent or the bandwidth to come to Tehran's aid in a military sense even though the suitability of the current political system under Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei is critical to their own individual interests.

#### Where Russia stands

For Moscow, its war against Ukraine has tied down most of its political and military capabilities. The other opaque member of the axis, North Korea, is already providing soldiers to Russia to arrest its depleting military depth. This denies it any capabilities to tactically help Tehran. Previously, with its bases and assets in Syria, providing some air power assistance could have been possible, at least theoretically. However, with the fall of the Assad regime, which has now been replaced by former al-Qaeda leader Ahmed Al Sharaa – ironically, he is prioritising relations with the West pushed by Arab partners – Moscow has lost the only military footing it had in West Asia.

China too has come out in support of Iran. While its Foreign Minister Wang Yi in a call with his Israeli counterpart highlighted how Israeli strikes were violating international law, a readout after a call between Mr. Xi and Mr. Putin interestingly demanded that the U.S. (without referencing it directly) orchestrate a de-escalation. While both Russia and China are worried about the wider implications of this conflict, it benefits their strategic postures in many ways. With the U.S. now having joined Israel in attacking Iran, a decision Mr. Trump took while keeping even his closest advisers in the dark, it would bog the White House down once again in West Asia, potentially relocating critical military assets away from the Indo-Pacific and from Ukraine. This would free-up space in both Beijing and Moscow's immediate geographies of interest while also potentially sowing self-inflicted discord within the Trump administration. For now, a brittle U.S.-backed ceasefire is holding Tehran and Tel Aviv at bay.

#### The outlook

For Iran, the news on any of the axes front is not good. While Russia and China may prioritise their own positions, the proverbial 'Axis of Resistance' made up of Hezbollah, Hamas, and the Houthis among others is down for the count as Iran's first line of defence and offence in the region. Finally, the future of Iran, irrespective of what kind of political reality prevails, even in a moderate system, may be shaped by the point that only nuclear power can hereon guarantee sovereignty.

## मुख्य विषय और मुद्देः

#### 1. रणनीतिक गठबंधनों का क्षरण:

यद्यपि रूस, चीन और ईरान के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारियाँ मौजूद हैं, यह संघर्ष इन संबंधों की गैर-बाध्यकारी और गैर-सैन्य प्रकृति को उजागर करता है। नाटो जैसे सुरक्षा समझौतों के विपरीत, इन रिश्तों में लागू करने योग्य सामूहिक रक्षा तंत्रों का अभाव है।





2. कूटनीतिक वक्तव्यों के ऊपर यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik):

रूस और चीन ने भले ही ईरान के प्रति कूटनीतिक सहानुभूति जताई हो, लेकिन दोनों ने सैन्य सहायता नहीं दी। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पहले से ही तनाव में है, जबिक चीन घरेलू आर्थिक स्थिरता और अमेरिका के भू-राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वह भी अधिक सूक्ष्म तरीकों से।

#### 3. 'अक्ष' की सीमाएँ:

तथाकथित "उथल-पुथल का अक्ष" या "प्रतिरोध का अक्ष" (जिसमें हिज़्बुल्लाह, हमास और हौथी जैसे गैर-राज्यीय अभिनेता शामिल हैं) को गंभीर रूप से कमजोर किया गया है। प्रतिबंधों, नेतृत्व की हत्याओं और क्षेत्रीय पुनर्सरेखण ने ईरान की रणनीतिक गहराई को कुंद कर दिया है।

4. अमेरिका के लिए भू-राजनीतिक परिणाम:

पश्चिम एशिया में अमेरिका की पुनः भागीदारी, अब यूक्रेन और मध्य पूर्व दोनों में उलझन के कारण, इंडो-पैसिफिक रणनीति पर उसका ध्यान कम कर सकती है, जिससे रूस और चीन को उनके आस-पास के रणनीतिक क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता है।

5. ईरान की रणनीतिक अलगाव:

ईरान अब बढ़ती सैन्य भेद्यता, आर्थिक कमजोरी और कूटनीतिक एकाकीपन का सामना कर रहा है। यहाँ तक कि पारंपरिक सहयोगी भी अब सहायता बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। इससे तेहरान को अधिक आक्रामक परमाणु नीति की ओर धकेला जा सकता है, जिससे परमाणु शक्ति को संप्रभुता की एकमात्र प्रभावी गारंटी के रूप में देखा जा सकता है।

6. मध्य पूर्व में पुनर्सरेखण:

सीरिया के नए नेतृत्व का पश्चिम की ओर झुकाव, रूस को उत्तर कोरिया द्वारा सैन्य समर्थन, और अरब देशों का ईरान से रणनीतिक दूरी बनाना—ये सभी क्षेत्रीय व्यवस्था के बिखरने का संकेत देते हैं, जिनके स्थिरता और गठबंधनों पर अनिश्चित परिणाम हो सकते हैं।

## व्यापक रणनीतिक और कूटनीतिक अंतर्दृष्टियाँ:

- तथाकथित पूर्वी अक्ष (रूस–चीन–ईरान) में औपचारिक सैन्य गठबंधनों का अभाव इसे कमजोर और कथानक आधारित बनाता है, न कि क्रियाशील।
- रूस और चीन द्वारा किया गया रणनीतिक संतुलन पारस्परिक सैन्य प्रतिबद्धता नहीं, बिल्क आर्थिक परस्पर निर्भरता और राजनीतिक सतर्कता को दर्शाता है।
- यह घटना समकालीन भू-राजनीति की लचीली प्रकृति को रेखांकित करती है, जहाँ शीत युद्ध युग के कठोर गठबंधनों की जगह अस्थायी, हित-आधारित संरेखण ने ले ली है।
- ईरान का भू-राजनीतिक भविष्य, विशेष रूप से उसके परमाणु हथियारों पर रुख, न केवल पश्चिम एशियाई सुरक्षा बिल्क वैश्विक अप्रसार बहस को भी आकार देगा।

#### निष्कर्षः

'उथल-पुथल का अक्ष' एक कार्यात्मक गठबंधन की तुलना में एक वैचारिक संरचना के रूप में अधिक सामने आया है। अपने सबसे संकटपूर्ण समय में ईरान का अलग-थलग पड़ना उसके रणनीतिक अनुमानों की कमजोरी और आधुनिक भू-राजनीति की लेन-देन आधारित प्रकृति को उजागर करता है। भारत और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह क्षेत्रीय भागीदारी, रणनीतिक स्वायत्तता और अनौपचारिक वैश्विक शक्ति संरचनाओं पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों पर पुनर्विचार करने का संकेत है। इस विकसित उत्तर-संघर्ष परिदृश्य में, राजनियक कुशलता और रणनीतिक स्पष्टता अत्यंत आवश्यक होगी।





#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: "ईरान-इज़राइल संघर्ष उभरते वैश्विक शक्ति ब्लॉकों की कमज़ोरी को उजागर करता है।" ईरान, रूस और चीन से मिलकर बने तथाकथित 'उथल-पुथल की धुरी' की प्रकृति और सीमाओं की आलोचनात्मक जाँच करें। (250 Words)

#### Page 09: GS 2: Indian Polity

भारत में बड़ी संख्या में आंतरिक प्रवासी, विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों से आने वाले लोग, चुनावों के दौरान प्रभावी रूप से मतदान से वंचित रह जाते हैं। कई चर्चाओं और प्रस्तावों के बावजूद, प्रवासी श्रमिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अब तक कोई समग्र तंत्र लागू नहीं किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार में मात्र 56% मतदान दर इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करता है।

## Enabling voting rights for migrants

ihar, a State with one of the largest out-migration populations in India, is going to the polls later this year. This time, again a significant proportion of the State's population will be unable to exercise their franchise.

In the 2024 Lok Sabha elections, voter turnout in Bihar was 56%, significantly lower than the national average of 66%. Since more than half the households in Bihar are exposed to migration in some form, a likely factor to have significantly influenced low voter turnout was the large migrant population, which was unable to return home to vote.

#### Patterns of migration

In 2021, the overall migration rate in India was 28.9%. A significant portion of migration in India is for marriage, especially among women. Around 10%, however, migrate for work. This number is significantly higher in certain northern and eastern States such as Bihar. With an ever-increasing number of migrants travelling from poorer to richer areas in search of employment, the number of those effectively disenfranchised will only increase, unless mechanisms are put in place to facilitate voting by migrants. In an attempt to solve the issue, public discussions have been held. The Election Commission of India (ECI) put forth a concrete proposal in 2024. But no single mechanism for voting for migrants has been implemented

Different kinds of policies and mechanisms are needed to enable voting for different kinds of migrants (intra and inter-State migrants). Intra-State migrants (around 85% of migrants) working in the informal sector could be encouraged to travel relatively shorter distances to vote in their original place of residence. However, they would need a measure of support from the government. Stricter enforcement of the statutory holiday on polling



Aman Rameshwar Krishna

Urban Fellow at the Indian Institute for Human Settlements, Bangalore

An approach

that combines

will enable a

of inter- and

intra-State

migrants to

exercise their

right to vote

several options

significant share

day would ensure that these workers are able to travel to vote without loss of wages. Special bus services could also be scheduled on the eve of and on polling day.

#### Different mechanisms

Inter-State migrants working in the informal sector are a large, growing and vulnerable population and need a different set of voting mechanisms. Three possibilities can be explored for this section. The first is an option designed to cater to the large population of migrants in irregular and low-paying jobs, such as in the construction sector. Workers in these jobs may not have permanent residences with address proofs. In 2023, the ECI showcased a pilot project of remote electronic voting machines (RVMs). Each of these was an EVM modified to cater to up to 72 constituencies. Political parties objected to this project. They said there was ambiguity over its functioning. They also cited issues such as problems in identification of migrants and the Code of Conduct being in place in the constituency where the migrant was residing. The project also appeared to be administratively difficult to implement at scale: when a large State with a large out-migration population goes to the polls, migrants from the State who currently reside across the country would be required to notify the ECI months in advance so that the ECI can make the necessary arrangements on polling day. If the ECI finds that in a given city, there are migrants from all 243 constituencies of Bihar, it would need to set up at least four RVMs across the city. The administrative difficulties would only be compounded during the Lok Sabha elections. As complex and challenging as the RVM proposal seems, it was the first major attempt by the ECI to facilitate voting for migrants. With more consultation and fine-tuning,

this system could benefit many.

Another option is postal ballots
This system is already being

implemented by the ECI for members of the armed forces. An extension of this model could help many migrants. Here, too, the ECI would require migrants to register with the body well in advance, so the postal ballots can be issued. Operationally, this appears to be the easier form of remote voting to implement. However, the ECI would have to organise registration, issue ballot papers, and despatch these ballots to counting centres after voting – all major administrative efforts.

The last option – switching voting constituencies – is suitable for the longer term for more permanent migrants who can prove their residence in a constituency for at least six months. The argument here is that longer-term migrants of an area would likely be more concerned about the politics and policies of their current place of residence. The ECI should also take extra effort to enrol longer-term migrants of the informal sector in their current place of residence. This will empower them to pressure governments to implement more migrant-friendly policies. While this move may face significant opposition from longer-term residents of the area, it would empower one of the most vulnerable sections of the population.

Separately, as a significant number of migrant populations across the country are women who migrate after marriage, voting drives could also be carried out to enrol these women on the voter lists of their new place of residence.

#### A mixed approach

Each of these options has its advantages and disadvantages. Enabling voting by migrants is a complex task and is made more complex by the heterogeneity of migrants. Therefore, an approach that uses all these options will enable a significant share of both inter- and intra-State salaried and casual migrants to exercise their right to vote.

**VISHV UMIYA FOUNDATION INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES (VUFICS)** 





## मुख्य मुद्देः

#### प्रवासन का पैमाना और विविधता:

2021 में राष्ट्रीय प्रवासन दर लगभग 29% थी, जिसमें से लगभग 10% लोग काम के लिए प्रवास करते हैं। भारत की आंतरिक प्रवासी आबादी विशाल और विविध है, जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर-जनपदीय दोनों तरह के प्रवासी शामिल हैं। इनकी गतिशीलता, निवास, पहचान और पते के दस्तावेजों तक पहुंच अलग-अलग होती है।

#### 2. प्रभावी रूप से मतदान से वंचित:

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासियों के पास मतदान के समय अपने गृह क्षेत्र में लौटने के लिए न तो आर्थिक संसाधन होते हैं और न ही समय। वे अक्सर मजदूरी गंवा देते हैं या यात्रा में अड़चनें झेलते हैं, जिससे उनकी प्रणालीगत उपेक्षा होती है।

#### 3. मतदान में असमानता:

प्रवासियों का मतदान नहीं कर पाना **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का उल्लंघन** है। यह अत्यधिक गतिशील और आर्थिक रूप से कमजोर आबादी को हाशिए पर रखता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र की समावेशिता कमजोर होती है।

## प्रस्तावित समाधान और उनकी चुनौतियाँ:

- 1. रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVMs):
  - 2023–24 में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित, जिससे प्रवासी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान कर सकें।
  - **चुनौतियाँ:** तकनीकी जटिलता, पहचान संबंधी समस्याएं, राजनीतिक विरोध, और उच्च प्रवासी घनत्व वाले शहरों में कई निर्वाचन क्षेत्रों के लिए RVMs स्थापित करने का भारी प्रशासनिक बोझ।

#### 2. पोस्टल बैलेट (डाक द्वारा मतदान):

- सशस्त्र बलों और कुछ अन्य वर्गों के लिए पहले से लागू। प्रवासियों के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकता है।
- चुनौतियाँ: पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता, बैलेट वितरण की प्रभावशीलता, सुरक्षा और समय पर गिनती सुनिश्चित करना।

### 3. मतदान क्षेत्र बदलना (पुनः पंजीकरण):

- ऐसे दीर्घकालिक/स्थायी प्रवासियों के लिए जो 6+ माह से निवास का प्रमाण दे सकते हैं। यह उन्हें कार्यस्थल या निवास स्थान की राजनीति में सक्रिय भागीदारी की ओर प्रोत्साहित करता है।
- चुनौतियाँ: सत्यापन में कठिनाई, स्थानीय निवासियों का प्रतिरोध, और राजनीतिकरण की आशंका।

## 4. राज्य के भीतर प्रवासियों के लिए सहायता:

- मतदान दिवस पर अवकाश लागू करना, विशेष परिवहन सेवाएं प्रदान करना।
- चुनौतियाँ: नीति कार्यान्वयन में बाधाएं, नियोक्ताओं का सहयोग, और प्रवासियों में जागरूकता की कमी।





#### 5. लैंगिक आयाम:

- विशेष रूप से विवाह के बाद प्रवास करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है जो नए निवास पर मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं होतीं। विशेष अभियान से इन्हें जोड़ा जा सकता है।
- चुनौतियाँ: सामाजिक मानदंड, दस्तावेजों की कमी, और जागरूकता का अभाव।

#### महत्व:

- प्रवासियों को मतदान का अधिकार देना चुनावी समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करता है।
- यह असंगठित और हाशिए के श्रमिकों को राजनीतिक दृश्यता देता है, जिससे सरकारों पर प्रवासी-अनुकूल नीतियाँ बनाने का दबाव बनता है।
- यह प्रतिनिधित्व और कानून के समक्ष समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखता है।

#### आगे की राह:

- **बहु-आयामी और संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण** अपनाएं—पोस्टल बैलेट, RVMs, और पुनः पंजीकरण को मिलाकर लागू करें।
- पायलट परियोजनाएं चलाएं, संस्थागत ढांचा तैयार करें, और अंतर-राज्य समन्वय को बढ़ावा दें।
- नागरिक समाज, नियोक्ताओं और स्थानीय प्रशासन को जागरूकता अभियानों और लॉजिस्टिक समर्थन में शामिल करें।
- शहरी शासन व्यवस्था में चुनावी समावेशन को प्राथिमकता दें, खासकर उन शहरों में जहाँ प्रवासियों की संख्या अधिक है।

#### निष्कर्षः

प्रवासी मतदाताओं का वंचन भारत की मजबूत चुनावी प्रणाली में एक गंभीर लोकतांत्रिक कमी का संकेत है। जैसे-जैसे आंतरिक प्रवासन बढ़ता जा रहा है, इस अंतर को पाटना न केवल एक नीतिगत आवश्यकता है बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। नवाचारपूर्ण, समावेशी और अनुकूल प्रणाली अपनाकर भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भावना को जीवंत रख सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई भी नागरिक उसकी गतिशीलता या आर्थिक कमजोरी के कारण अनसुना न रह जाए।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: "आर्थिक रूप से आवश्यक होने के बावजूद प्रवासी राजनीतिक रूप से अदृश्य हैं।" भारत के वर्तमान चुनावी ढांचे के प्रकाश में इस विरोधाभास का विश्लेषण करें और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक समावेशी बनाने के तरीके सुझाएँ। (250 Words)





#### Page: 10: GS 2: Social Justice

भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना 2027 में की जाएगी, और 1941 के बाद पहली बार इसमें जातिगत गणना भी शामिल की जाएगी। इस निर्णय ने यह बहस फिर से शुरू कर दी है कि क्या भारत की वर्तमान जनगणना संरचना ऐसे अर्थपूर्ण जाति-आधारित सामाजिक-आर्थिक डेटा का उत्पादन करने में सक्षम है, या हाशिए पर पड़े समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए गंभीर पुनर्रचना की आवश्यकता है।

## Should the method of counting caste change?

What are the two phases of the Census? Why has caste enumeration been included in the upcoming Census, according to the Union government? What are the reforms the Census should undertake in order to facilitate data that will be helpful for bringing the marginalised to the mainstream?

#### EXPLAINER

#### K. Narayanan Unni

The story so far:

he Central Government has announced that the next 1 announced that the next Census would take place in 2027 and that it would collect information on castes. Can such a massiv data exercise be made more useful through a restructuring of the existing Census process?

How is the Census conducted? How is the Census conducted? The first phase of the Census, called house-listing, would probably be conducted between April to September in 2026. This stage lists all the dwelling units in the country where people live, along with several characteristics of the houses and households.

The second phase called the The second phase called the population enumeration phase would be conducted in 2027, wherein information on several key socio-economic characteristics of the population would be collected. This is also the stage where caste would be recorded.

Why is caste being recorded?
The recording of an individual's caste was last done in the 1941 Census. However, that data could not be processed due to economic constraints of the Second World War. Thus, effectively, the last Census to provide data on case has been the 1931 Census that has become too outdated to use for any purpose. Prime Minister Narendra Modi is reported to have said that caste enumeration as part of the Census is a step the government is taking to bring the marginalised and those left behind in every field into the mainstream. However,

every field into the mains given the limitations of the Census as a method of data collection as well as the design of the Census questionnaire, it is doubtful whether this objective can be fulfilled. A restructuring of the Census questionnaires could make more useful questionnaires could make more useful data be made easily available to further the objectives indicated by the Union

questionnaires?
It is presumed that the questions that were included in the draft questionna for the 2021 Census may more or less remain the same for the 2027 Census. In the 2021 draft, the question on caste was

restricted to those belonging to Scheduled Castes (SQ) as in the past Censuses.

By making this question applicable to all castes, except Scheduled Tribes (ST), and with consequent changes in instructions and the software used for instructions and the software used for electronic data collection, data on cases can be collected. The practical difficulties collecting data on castes is not within the scope of this article. Information on specific castes can be ascertained through literacy/educational levels; age at marriage; mother tongue and other languages known; status of the individual as the main worker, marginal worker on non worker; seeking/available for work; broad classification of industry/occupation of the worker, place of birth pre-volume residence; and data on child birth and survival.

child birth and survival.

While the data on 'mother tongue and other languages known' may not be of much importance in assessing the socio-economic status of various castes, information on participation in economic activity and its broad classification may be of use. However, the data on



unemployment derived using the response to the question "whether seeking/available for work" suffers from conceptual issues and lack of attention in the attention to recomple, the attention to recomple, and the attention to recomple, and the attention to recomple, and one year. However, it is not clearly mentioned as to how long a person should be seeking/or be available for work to be cleasified as unemployed. Though this question has been asked in every Census starting from 1981, it could never give useful data.

Information on 'child births and survival' collected in the Census suffers from serious quality issues. These unemployment derived using the

survival\* collected in the Census suffers from serious quality issues. These questions, included in the Census from 1981, have outlived their utility as similar information is better collected through the National Family Health Surveys. Getting any reliable caste-wise data from these questions is almost impossible. Information on migration may be an important aspect to assess whether people of certain castes are more prone to migration. However, data from

Important sep-people of certain castes are more prone to migration. However, data from previous Censuses seem to indicate that a large percentage of migrants are not counted or are no recorded as migrants. Thus, the only information that voide a vailable to classify caste are those of education, age at marriage and participation in economic area.

education, age at marriage and participation in economic activity. While the Census does collect other information that would help in moving towards the objectives stated by the Union government for the inclusion of caste in the Census, it would need some serious restructuring of the Census questionnaires and process. questionnaires and process.

How should the Census questionnaires be restructured? The main objective of the house listing phase is to prepare a list of all dwelling units where people are living or are likely

to be living at the time of the Census. This framework helps in carving out nev iraniework neips in carving out new enumeration blocks as required and thus helps balance the workload of the enumerators. Several questions relating to quality of housing, amenities available to households and assets owned, have been asked during this phase from the 1991 Census onwards.

asked during this phase from the 1991 Census onwards. However, in the 1981 Census, these questions were in the household schedule canvassed during the second phase of the census, that is the population enumeration phase. Transferring these questions from the house list schedule to the household schedule would help linking information on quality of housing, amenities and assets to other aspects of the population easier. As there is a time gap of six to nine months between the house-listing and population enumeration phases, linking the information on the basis of house number, name of the head of the number, name of the head of the number, name of the head of the household etc. may bring about error. Such errors may seriously impact the reliability of data, especially for small

communities.
Taking the questions out of the house-listing schedule would also help enumerators to concentrate on the listing of all buildings, be it residential, partly of all buildings, be it residential, partly residential or non-residential along with the number of people living in them. Improved house-lists would help in better coverage of the Census. This is very important in urban areas which have higher omission rates in most Censuses. Such linkages or transfer of questions have not been adopted in either the 2011 Census or in the planning of the planning of the COVID-19 pandemic).
Without such data in the Census, it is not possible to answer questions like,

not possible to answer questions like,
"What is the literacy rate of persons living

whether this is significantly lower than that of others" or "What proportion of the workforce in urban areas live in kutcha

workfore in urban areas live in kutcha houses?", etc.
The Census should be able to provide answers to the above questions, disaggregated by caste. Then only can the data be used for identifying marginalised communities and the extent of disparities between them. Though collecting accurate data through a Census on many of these variables is not an easy process, and though the quality of data might suffer, it is the best alternative as of now.

Should some questions be omitted? There is a need to make the Census leaner There is a need to make the Census leaner by dropping unnecessary questions. Several questions on amenities available to the house-hold or assets owned by them may have become redundant. For example, ownership of mobile phones or that of computers may not be as aimportant now as it was five years ago. Similarly, questions on access of households to bank accounts might be omitted. A shorter questionnaire would help the enumerator concentrate on getting more accurate responses to the questions.

The Census has been providing

questions.

The Census has been providing The Census has been providing caste/ribe wise data on several socio-economic variables. It is doubtful whether this data have been used to identify the most backward castes/ribe for similar exercises that could aid of policy/program formulation. Hopefully, caste-wise data thrown up by the upcoming Census would be used better in policy and program formulations, and be used beyond decisions regarding the percentages for reservation.

The author is a retired officer from the Indian Statistical Service and a former Deputy Registrar General.

#### THE GIST

is reported to have said that caste enumeration as part of the Census is a step the government is taking to bring the marginalised and those left behind in every field into the

Information on migration may be an important aspect to assess whether people of certain castes are more prone to migration. However, data from previous Censuses seem to indicate that a large percentage of migrants are not counted or are not recorded as migrants.





#### मुख्य मुद्दे:

#### 1. जातिगत आंकडों में ऐतिहासिक अंतर:

अंतिम व्यापक जातिगत डेटा 1931 में एकत्र किया गया था, जिससे उस पर आधारित कोई भी नीति आज के संदर्भ में अप्रासंगिक हो गई है। 2011 में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) की गई थी, लेकिन गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं के कारण इसके डेटा को सार्वजिनक नहीं किया गया। आगामी जनगणना इस महत्वपूर्ण डेटा अंतर को भरने का एक नया अवसर प्रस्तुत करती है।

#### 2. जाति गणना का उद्देश्य:

सरकार का तर्क है कि जातियों की गणना करने से हाशिए के समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। हालांकि, आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि क्या वर्तमान जनगणना ढांचा इस उद्देश्य को समर्थन देने के लिए पर्याप्त, विस्तृत और व्यावहारिक डेटा प्रदान कर सकता है।

#### वर्तमान जनगणना डिज़ाइन की संरचनात्मक सीमाएँ:

1. प्रश्नावली की सीमित प्रकृति:

2021 के मसौदा कार्यक्रम में, जाति से संबंधित प्रश्न केवल अनुसूचित जातियों (SC) तक सीमित थे, जबिक OBC और अन्य जातियों को शामिल नहीं किया गया था। पूर्ण जाति स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी जातियों (ST को छोड़कर, जिनकी गणना पहले से होती है) से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाए।

## 2. प्रश्नों की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याएँ:

कुछ मौजूदा प्रश्न अवधारणात्मक अस्पष्टता और प्रासंगिकता की कमी से ग्रसित हैं, जैसे:

- बेरोज़गारी: "क्या कार्य की तलाश में/उपलब्ध हैं" जैसे प्रश्न अस्पष्ट हैं और खराब डेटा प्रदान करते हैं।
- जन्म और बाल जीवितता: यह डेटा NFHS जैसे सर्वेक्षणों से बेहतर ढंग से प्राप्त होता है।
- संपत्ति या मोबाइल/बैंक खाते की उपलब्धता: यह अब सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक संकेतक नहीं माना जा सकता।

#### 3. डेटा को जोड़ने में कठिनाई:

हाउस-लिस्टिंग और जनसंख्या गणना चरणों के बीच 6–9 महीने का अंतर होता है, जिससे संपत्ति की जानकारी को जाति, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने में त्रुटियाँ हो सकती हैं — विशेषकर छोटे या कमजोर समुदायों के लिए।

## 4. शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त कवरेज:

शहरी क्षेत्रों में अक्सर उच्च दर से गणना त्रुटियाँ होती हैं, जिससे वहां जाति और सामाजिक-आर्थिक संबंधों से संबंधित डेटा की विश्वसनीयता घट जाती है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अधिक गतिशील या दस्तावेजविहीन होते हैं।

#### सुधार के सुझाव:

### 1. प्रश्नावली का पुनर्रचना:

- **आवास की गुणवत्ता, सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े प्रश्नों** को जनसंख्या गणना चरण में स्थानांतरित करें ताकि डेटा को आसानी से जोड़ा जा सके।
- अप्रासंगिक प्रश्नों को हटाकर प्रश्नावली को संक्षिप्त और केंद्रित बनाया जाए।





• रोजगार और प्रवासन से संबंधित प्रश्नों को अधिक स्पष्ट और उपयोगी बनाया जाए।

#### 2. जातिवार डेटा लिंकिंग:

जनगणना का उद्देश्य जाति को शिक्षा, रोजगार, आवास जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों से जोड़ना होना चाहिए ताकि वंचित वर्गों की पहचान की जा सके और उन पर लक्षित नीतियाँ बनाई जा सकें।

3. डेटा के उपयोग में सुधार:

जनगणना लंबे समय से जाति/जनजाति-वार डेटा तो देती रही है, लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर आरक्षण तय करने तक सीमित रहा है। भविष्य में इसका उपयोग सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान और समावेशी विकास कार्यक्रमों की योजना में किया जाना चाहिए।

#### महत्त्व:

- बेहतर ढंग से डिज़ाइन की गई जाति गणना से:
  - रोज़गार, शिक्षा, आवास और प्रवासन में अंतर-जातीय असमानताओं की पहचान की जा सकेगी।
  - समावेशी विकास के लिए लिक्षत नीतियाँ बनाना संभव होगा।
  - जातिगत बहस को **पहचान आधारित राजनीति से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण** की ओर ले जाया जा सकेगा।

#### निष्कर्षः

2027 की जनगणना में जाति को शामिल करने का निर्णय समावेशिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन वर्तमान जनगणना संरचना अर्थपूर्ण और उपयोगी जातिगत डेटा प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रश्नावली, कार्यप्रणाली और डेटा उपयोग की पद्धित में समग्र पुनर्रचना अनिवार्य है। अन्यथा, जाति गणना सिर्फ प्रतीकात्मक अभ्यास बनकर रह जाएगी, निक सामाजिक परिवर्तन और न्याय का उपकरण।

#### **UPSC Mains Practice Question**

Ques: "जनगणना को जनसांख्यिकीय अभ्यास से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विकसित होना चाहिए।" आगामी 2027 की जनगणना में जाति गणना को शामिल करने के संदर्भ में चर्चा करें। (250 words)





## **Page: 08 Editorial Analysis**

# A lofty concept, a Governor and unwanted controversy

picture of 'Bharat Mata' (Mother India) has triggered a confrontation between the Governor of Kerala and the State government. At a recent function, the Governor had placed a painting of Bharat Mata in the form of a female figure clad in a saffron colour sari with a spear in one hand and standing with a lion behind her against a backdrop of the map of India. The painting had been placed in a room where official functions are held at Raj Bhavan. A tall brass lamp was placed before this garlanded picture. Before any official function begins, the Governor bows before it, offers flowers and lights the lamp. The Chief Minister and other Ministers had raised objections on the grounds that this picture of Bharat Mata is not recognised by the Constitution or any law unlike the national anthem of India or the national flag or other national symbols. Therefore, the government seems to have taken a position that it will not participate in any official function organised by the Governor where this picture is displayed.

The slogan, 'Bharat Mata ki Jai', was the emotional cry of freedom fighters which would electrify the minds of people who were fighting for freedom from colonial rule. And, they used to raise this slogan at the highest pitch when they were subject to lathi blows. Thus, Bharat Mata is one that deeply resonated with the countless millions during India's freedom struggle.

But the question in this issue in Kerala is not whether we should pay obeisance to this image of Bharat Mata. There is no doubt that Indians have a deep and emotional bond with the concept of Bharat Mata. However, in the Kerala episode, the issue is that the Governor has and uses a picture of what is claimed to be Bharat Mata at the venue where official functions organised by the government are held and offers floral tributes to it as a part of the official function.

#### The conduct of the Governor

Since no picture of Bharat Mata in any form has been recognised by either the Constitution or any law or adopted like the national anthem, the national flag, the national emblem or even the national symbols, such a picture cannot be a part of any official function organised by the government. It may be noted here that this picture of Bharat Mata is used only by the Rashtraiya Swayamsevak Sangh and the Bharatiya Janata Party in their functions. The Governor,



P.D.T. Achary
is former Secretary
General, Lok Sabha

being the constitutional head of the state, is expected to conduct himself in accordance with the Constitution. The Governor cannot take independent decisions in the performance of his duties and functions but can act only in accordance with the advice of the elected government. So, if the government decides that such pictures should not be placed at the venue of official meetings organised by the government, the Governor is required to go by that decision.

The personification of Bharat Mata as a mother figure was first done by renowned Bengali novelist, Bankim Chandra Chattopadhyay, in his late 19th century work, *Anandamath*. But the mother symbol he created was Banga Mata (Mother of Bengal) – and not Bharat Mata – and it became the powerful symbol of Bengali nationalism.

But it was Abanindranath Tagore, the nephew of Rabindranath Tagore who first did a painting of the Banga Mata in 1905. This depiction, with four arms, in some ways resembled a Hindu goddess. It was sister Nivedita, a prominent disciple of Swami Vivekananda, who popularised this painting as Bharat Mata. Later, 'Bharat Mata ki Jai' became the most powerful slogan of the national freedom movement but without any visual representation. The national movement never adopted any picture of the Bharat Mata.

A lofty concept

No one has defined the concept of Bharat Mata as brilliantly as Pandit Jawaharlal Nehru. He explains it in his inimitable style in his Discovery of India: "...sometimes as I reached a gathering a great roar of welcome would greet me: Bharat Mata ki Jai-Victory to Mother India. I would ask them unexpectedly what they meant by that cry, who was this Bharat Mata, whose victory they wanted ..... The mountains and the rivers of India and the forest and the broad fields which gave us food were all dear to us, but what counted ultimately were the people of India, people like them and me who were spread out all over this vast land. Bharat Mata, Mother India, was essentially these millions of people and victory to her meant victory to these people.'

It is rather unfortunate that this lofty concept of Bharat Mata has triggered an unseemly controversy involving the Governor of Kerala. Obviously the picture of a female figure in a saffron sari, with a spear in hand and a lion behind her, cannot be a symbol of Bharat Mata. The display of such a picture is a throwback to 19th century nationalism which has no relevance in modern times. Indian nationalism under Gandhi had a strong secular core and was inclusive. Anthropomorphisation of a country is an outdated idea. The diversities, the divisions of Indian society, multiple religions, races, and different levels of cultural developments cannot be represented by such a figure.

#### Governor versus the government

The country has witnessed too many unseemly fights between Governors and State governments. The Supreme Court of India has intervened in some cases and tried to set things right. Nevertheless the Governor-government spats continue to occur. The Constitution and the interpretations thereon by the Supreme Court have clearly laid down the limits of a Governor's powers and functions. Dr. B.R. Ambedkar had said emphatically in the Constituent Assembly, "the governor under the constitution has no functions which he can discharge by himself, no functions at all."

The Raj Bhavan Kerala controversy, deliberate or otherwise, was absolutely unnecessary. It sours the relationship between the Governor and the elected government. In official functions, symbols or logos or other visual representations used by private organisations cannot be used. Raj Bhavan does not merely consist of the private chambers of the Governor. There are rooms and halls where government functions are held such as a swearing-in ceremony as it is done in Rashtrapati Bhavan.

The Governor is bound by the advice of the government on, for example, the placing of photographs, portraits in such places and also of performing various actions in an official function such as the lighting of the lamp as in protocol approved by the government. The Governor, for example, cannot order that the picture of Bharat Mata should be placed in all government offices. It is a decision only the government can take. All constitutional authorities are bound by the disciplines of the Constitution. The government has the constitutional right to advise the Governor not to place the picture of Bharat Mata at venues used to conduct official meetings on the ground that such a picture has not been recognised by the Constitution or statutes.

and emotional bond with the concept of Bharat Mata, but all constitutional authorities are bound by the framework of the Constitution

There is a deep

Paper 02: Indian Polity

UPSC Mains Practice Question : "राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख है, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं।" राज्यपालों और राज्य सरकारों से जुड़े हाल के विवादों के आलोक में, राज्यपाल की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाओं की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)





#### **Context:**

हाल ही में केरल में एक विवाद तब उत्पन्न हुआ जब राज्यपाल ने राजभवन के एक आधिकारिक कक्ष में 'भारत माता' की एक तस्वीर लगाई और आधिकारिक समारोहों की शुरुआत उस पर पुष्पांजिल अर्पित करके करने लगे। निर्वाचित राज्य सरकार ने इस पर आपित जताई, यह तर्क देते हुए कि इस प्रकार का प्रतीक न तो संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है और न ही किसी कानून द्वारा अनुमोदित, जिससे राज्यपाल की शक्तियों की सीमा और सार्वजिनक संस्थानों में गैर-मान्यता प्राप्त प्रतीकों के उपयोग को लेकर बहस छिड़ गई।

## मुख्य मुद्देः

- प्रतीकों की संवैधानिक मान्यताः
  - राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीक के विपरीत, 'भारत माता' की किसी विशेष छवि को संविधान या कानून द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। 'भारत माता की जय' का नारा भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवश्य है, परंतु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका कोई निर्धारित दृश्य रूप नहीं था, और इसे आधिकारिक रूप से राज्य द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया।
- 2. राज्यपाल का आचरण और संवैधानिक सीमाएं:

अनुच्छेद 163 और न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार, राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है। सुप्रीम कोर्ट और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्यपाल को स्वतंत्र कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ऐसे में, एक गैर-आधिकारिक प्रतीक को एक सरकारी स्थान पर स्थापित करना और सम्मान देना संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

- 3. सरकारी मंचों पर धार्मिक/सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग:
  - भारत माता की देवी स्वरूप छवि, विशेष रूप से भगवा वस्त्रों में और शेर के साथ, एक विशिष्ट सांस्कृतिक और वैचारिक समूहों (जैसे RSS, BJP) से जुड़ी मानी जाती है। ऐसी छवियों का सरकारी कार्यक्रमों में प्रदर्शन **भारत के धर्मिनरपेक्ष और बहुलतावादी संविधान के सिद्धांतों पर प्रश्न खड़ा करता है**, और कुछ समुदायों कोक्क्र कर सकता है।
- 4. भारत माता की ऐतिहासिक अवधारणा का विकास:
  - 'भारत माता' का विचार साहित्य और स्वतंत्रता आंदोलन में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 'बंगा माता' से हुई और फिर अबनींद्रनाथ ठाकुर की पेंटिंग से इसे दृश्य रूप मिला, जिसे सिस्टर निवेदिता ने लोकप्रिय बनाया। लेकिन यह हमेशा एक **रूपकात्मक अवधारणा** रही — न कि कोई आधिकारिक या कानूनी रूप से स्वीकृत प्रतीक।
- 5. संघीय संबंधों पर प्रभाव:
  - यह विवाद केंद्र और राज्य के बीच गहराते टकरावों का संकेत है, विशेष रूप से राजनीतिक मतभेदों के कारण। इस प्रकार की घटनाएं **सहकारी संघवाद** (cooperative federalism) को कमजोर करती हैं और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों की **निष्पक्षता और गैर-पक्षपातपूर्ण भूमिका** पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

#### संवैधानिक और प्रशासनिक प्रभाव:

• राज्यपाल एक **नाममात्र प्रमुख** होते हैं, जिन्हें संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करना चाहिए और किसी राजनीतिक रूप से उत्तेजक कार्य से बचना चाहिए।

#### **DAILY CURRENT AFFAIRS**





- सार्वजिनक संस्थानों को केवल संवैधानिक या वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतीकों और परंपराओं का उपयोग करना चाहिए।
- यह विवाद दर्शाता है कि राज्यपालों के आचरण और धार्मिक या सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, ताकि धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक तटस्थता की रक्षा की जा सके।

#### निष्कर्षः

केरल में भारत माता को लेकर उत्पन्न विवाद केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि एक गंभीर संवैधानिक और संघीय मुद्दा है। जबिक भावनात्मक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियाँ लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती हैं, सार्वजनिक संस्थाओं को संवैधानिक अनुशासन और प्रतीकात्मक निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। राज्यपाल, एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में, इस प्रकार के मामलों में राज्य सरकार की सलाह के ऊपर नहीं हो सकते और उन्हें एक तटस्थ सेतु की तरह कार्य करना चाहिए, न कि विवाद के स्रोत के रूप में। इस संतुलन को बनाए रखना भारत में धर्मिनरपेक्षता, सहकारी संघवाद और संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए अनिवार्य है।